Now, Statutory Resolution and The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017. Dr. Subbarami Reddy. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, we have raised this issue. मेधा पाटेकर को ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You raise it. It is there. ...(*Interruptions*)... Dr. Subbarami Reddy. ...(*Interruptions*)....

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रुपाला): सर, यह नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: उनका कसूर क्या है? ...(**व्यवधान**)...

श्री अली अनवर अंसारी: सर, महिलाओं पर लाठी चार्ज हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... यह क्या है? ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, we have raised this issue. मेधा पाटेकर को ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You raised it. It is there. ...(*Interruptions*)... Dr. Subbarami Reddy. ...(*Interruptions*)....

श्री परषोत्तम रुपाला: सर, यह नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: उनका कसूर क्या है? ...(**व्यवधान**)...

श्री अली अनवर अंसारी: सर, महिलाओं पर लाठी चार्ज हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... यह क्या है? ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Subbarami Reddy to move ...(*Interruptions*)...

STATUTORY RESOLUTION

The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 1 of 2017)

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move the following Resolution:–

> "That this House disapproves the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 1 of 2017), promulgated by the President of India on the 4th May, 2017."

GOVERNMENT BILL

The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, allow me to speak. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may speak when... ...(*Interruptions*)... There is no need for speaking now. ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: No, Sir. I want to speak now. ...(*Interruptions*)... Let me say why I am objecting to this. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you an opportunity to speak in the end. ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I must say why I am objecting. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Before putting it to vote, I can give you time. ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, let me start and conclude it within two-three minutes. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Take three minutes. ...(*Interruptions*)... Please sit down. I have taken up... ...(*Interruptions*)... Dr. Subbarami Reddy, three minutes. ...(*Interruptions*)... Nothing else will go on record. ...(*Interruptions*)... Only what Dr. Subbarami Reddy says will go on record. ...(*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश):*

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रुपाला):*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I allowed him. Let him speak.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I would like to know why the Government is resorting to this method again and again. Why should they bring an Ordinance, the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017, on 4th May, 2017, when the Session was about to be convened in July? Two months में क्या फर्क पड़ता है? I want to understand that and seek that clarification. The Government could have very well waited for the current Session and introduced this Bill in the Parliament. For dealing with the stressed assets, the Government had a lot of options, both legal and non-legislative loan recovery processes. They could have done loan restructuring, corporate debt restructuring, joint lenders forum, 5:25 scheme, strategic debt restructuring and sustainable structuring of stressed assets. I would like to know about the Debt

* Not recorded.

[Dr. T. Subbarami Reddy]

Recovery Tribunals, DRTs, a provision that is invoked for recovery of debts due to banks and financial institutions. There was the SARFAESI Act, under which assets restructuring companies could have taken over the assets. The Government says that there is a high percentage of Non Performing Assets. Now, here I would like to say that there are two types of NPAs. The first kind is caused when people intentionally run away and don't repay money to the banks. The second type of NPAs occur when industries like textiles, steel, cement, sugar are in a bad shape financially and temporarily unable to repay loans. There may be times when these industries can come up, but when there is stress in such industries and they are not able to repay money to the banks, they become NPAs. Therefore, I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to consider this very important matter. These NPAs are creating a wrong impression among the public. It is not right that every bank has got NPAs worth six or seven lakhs of rupees. They must classify the NPAs as those resulting from intentional misuse by industrialists or by people who have temporarily got stuck due to stress in the industry.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Thank you.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Just one minute, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That is all right. तीन मिनट्स हो गए। ...(**व्यवधान**)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, people talk for one hour; I am taking just two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Regarding the Bill that is under consideration, the Reserve Bank of India may issue directions to the banks to go in for insolvency. Now, they should first appoint an insolvency commission, which forms creditors committees and then the creditors committees together may take a decision on the banks. Of course, I fully agree that the ultimate arbitrator is the National Company Law Tribunal. Under Insolvency Code, there is a provision to settle the matter within 180 days. So, there is a time-bound resolution of an insolvency problem. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I have been in Parliament for the last 21 years. I never waste time; I never disturb. अच्छे आदमी को आप बोलने नहीं देते ...(*Interruptions*)... Why am I objecting? Ordinance is very important. As per the Constitution of India,

you have the right to bring it. At the same time, when you have two months to go for the Parliament Session, why did you hurry to bring the Ordinance in the month of May? Please clarify this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Arun Jaitley, move the Bill.

THE MINISTER OF FINANCE; THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS; AND THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move:–

> That the Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, we all know that the banking sector today is suffering from a serious problem of NPAs. पूरे बैंकिग सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर बैंक की स्थिति इसमें ज्यादा नाजुक इसलिए है कि जितने भी बड़े औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम होते हैं, उनमें पब्लिक सैक्टर बैंकिग का सपोर्ट ज्यादा रहता है। इसकी तुलना में जो प्राइवेट सैक्टर बैंकिग है, वह रिटेल बैंकिग की तरफ ज्यादा लोन देते हैं। मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता कि कब दिए, क्यों दिए, लेकिन इसके पीछे अगर गंभीरता से देखें तो जो मूल कारण है कि कुछ सेक्टर्स ऐसी इकोनॉमी के थे, जब विश्व में बूम पीरियड आया जिनमें एक्सपेंशन हो रहा था और वह पीरियड 2003 से लेकर 2008 तक का था और उसके बाद स्वाभाविक रूप से 2008-2009 में अर्थव्यवस्था की अपेक्षा यह होगी कि इस सेक्टर का काफी विस्तार होगा और इसलिए लोगों ने उस सेक्टर में आकर काफी निवेश भी किया, जिसके लिए स्वाभाविक रूप से बैंकों ने उसको खूब पैसा दिया। विश्व में कमोडिटी प्राइसेज सडनली गिर गए और उसकी वजह से अपने आप में एक प्रकार से इनको चुनौती मिलने लगी। सबसे अधिक जो एनपीए है, वह स्टील सेक्टर का है। स्टील सेक्टर में जो एनपीए है, उसका बुनियादी कारण यह था कि चाइना से सस्ता स्टील भारत में और दुनिया के दूसरे देशों में आने लग गया, जिससे कि हमारी स्टील की कम्पनियां अपनी क्षमता के मुताबिक स्टील की पैदावार नहीं कर पाईं। सरकार ने चाइनीज़ स्टील के ऊपर कई कदम उठाए। हम लोगों ने उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ायी और उसके बाद एक मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस लगाया, जिससे कि आज की तारीख में वह स्ट्रेस थोड़ा सा कम हुआ है और स्टील सेक्टर एक प्रकार से ट्रैक पर वापस आने लगा है। दूसरे नम्बर पर जो एनपीएज़ हैं, वे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के पीछे परिस्थिति यह थी कि कोई लीगल मेकेनिज्म उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने का नहीं था। देश में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनीज़ इस प्रकार की थीं जिन्होंने जिनके लिए काम किया, विशेष रूप से सरकारी संस्थाओं के लिए, उनके साथ लिटिगेशन चल रहा था। कुछ अवार्ड्स चेलेंज्ड थे या आर्बिट्रेशन में पैंडिग थे और बैंको को जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनीज़ को देना था, वह ब्याज बढ़ता जा रहा था, यह पिछले आठ-नौ साल से इसी प्रकार से चलता आ रहा था। हम लोगों ने एक नीति बनाई कि जिसके पक्ष में अवार्ड हो जाएगा उसको 75 परसेंट पैसा सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया जा सकता है, ताकि कारोबार चलता रहे और स्थिति में थोड़ा सुधार आए। इसमें रोड सेक्टर की जो कम्पनीज़ हैं, उनमें अब थोड़ा सा सुधार आया है, क्योंकि रोड के प्रोजेक्ट एक बार दोबारा से शुरू हो गए हैं। इसमें तीसरा सेक्टर बिजली का था। बिजली के सेक्टर में दो प्रकार की कम्पनीज़ थी, जिनके अंदर यह स्ट्रेस ज्यादा आया। एक जो राज्य सरकारों की State Discoms थीं, State Discoms की परिस्थिति इस प्रकार की थी कि कई राज्यों में लगता था

[Shri Arun Jaitley]

कि राजनीतिक लाभ की दृष्टि से हम सब्सिडाइज्ड, सस्ती बिजली किसी प्रकार से उपभोक्ताओं को देने लग जाएं और जो बिजली की कीमत है उनसे वसूल न करें और उसके पीछे कई राज्य सरकारों में यह लोभ भी था कि सस्ता देंगे, दर नहीं बढ़ाएंगे तो उससे लोकप्रियता बढ़ेगी। अब वह कितनी बढ़ती है यह अपने आप में एक प्रश्नचिन्ह था। लेकिन वह सारी जो Discoms थीं, अपने आप में उनके एनपीएज़ आसमान तक पहुंच गए। ऐसे राज्यों के उदाहरण भी हैं कि 5 साल के लिए सरकार बनी, जब 5 साल की सरकार आरम्भ हुई तो Discoms ने बैंकों का 15 हजार करोड़ रुपया देना था और क्योंकि उपभोक्ताओं से पैसे नहीं लिए तो 5 साल के बाद वह 60-65 हजार करोड़ हो गया। उससे वे पांच साल बाद चुनाव जीते नहीं, जिसका अर्थ यह है कि उससे लोकप्रियता तो ज्यादा बढ़ी नहीं, लेकिन पॉवर सेक्टर की कम्पनीज़ अपने आप NPAs की तरफ चली गयीं। अब उसमें Ministry of Power UDAY Bonds लेकर आयी, जिसमें कि राज्य सरकारों ने उस debt को अपने debt के अंदर लिया। फिर, वे धीरे-धीरे अपनी दर बढ़ायें, ताकि commercial constructions पर Discoms अपने आपको ऑपरेट कर पाएं।

पॉवर सेक्टर में ही एक दूसरा संकट आया, जब यूपीए सरकार के दौरान कोल माइन्स दिए गए, तो लोगों को लगता था कि economy का expansion हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कोल माइन्स देने के बाद पॉवर सेक्टर का expansion होगा। सुप्रीम कोर्ट में सारी litigation हुई और विवाद हुआ, वह एक प्रकार से विवाद का हिस्सा बन गया। उसके बाद उसका दूसरा पक्ष यह था कि जो हमारे यहां renewable energy है, उसका दाम कम होता गया। अगर आज आप सोलर के माध्यम से प्रोडक्शन करेंगे, तो वह पॉवर की तुलना में ज्यादा सस्ती पड़ेगी। पहली बार देश में ऐसी स्थिति आई, जब पॉवर की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई और उस पॉवर को खरीदने वाले इस वक्त कम हैं।

चौथा, टेक्सटाइल सेक्टर की थोड़ी समस्या थी। इसके लिए continuously, RBI आज नहीं, यूपीए सरकार के समय से इसका संचालन करता था, तो restructuring debt, S4A-RBI एक के बाद एक स्कीम को लाकर उसके लिए प्रयास करती रही कि किसी न किसी तरह से इसका हल निकले। दूसरा, इसका प्रयास यह था कि हम लोगों ने DRT का कानून भी अमेंड किया था ताकि उसके procedure simplify कर दिए जाएं। Securitisation Act में जो ARCs (Asset Reconstruction Companies) की स्थापना थी, उस कानून को liberalise किया ताकि Asset Reconstruction Companies आ जाएं और इनमें से अगर किसी का मैनेजमेंट बदल दिया जाता है, तो इसको टेकओवर करने की कैपेसिटी रखने वाली संस्थाएं बनें। वह प्रक्रिया आरंभ हुई है। देश में कई ARCs इस प्रकार से establish हुई हैं।

हम लोग insolvency law भी लेकर आए, लेकिन insolvency law के बाद भी देखा गया कि जितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे और ये वे प्रोजेक्ट्स हैं, जो किसी छोटे किसान या farm debt या छोटे स्टूडेंट्स लोन हैं, उनके साथ नहीं है, बल्कि जो इन चार-पांच सेक्टर्स के बड़े debts हैं, जो हजारों करोड़ में एक-एक कम्पनी का debt जाता है, उसमें multiple lenders हैं; कोई lender settle करने को तैयार है और कोई lender settle करने को तैयार नहीं है। बैंकों के प्रशासन कई बार इस बात से भी घबराते हैं कि अगर commercial considerations के ऊपर हमने settle

4.00 P.M.

किया, तो उसका बैंक के मैनेजमेंट और अधिकारी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यह आज की हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था है, हमारे laws and accountability mechanisms हैं। इसलिए एक और parallel mechanism, ये mechanisms हैं, लेकिन इन mechanisms के माध्यम से इनकी गति बहुत धीमी है और दूसरे उनको लगता है कि कौन आएगा, जो इस प्रकार की कम्पनी है, जिसको मौजूदा मैनेजमेंट चला नहीं पा रहा है, जिसमें कोई नये फंड्स नहीं डाल पा रहा है, जिसमें कोई joint venture नहीं ला पा रहा है, तो इसमें कौन मैनेजमेंट आएगा। Insolvency law के लिए एक समय-सीमा में, 180 दिन में एक resolution ढूंढ़े, इसकी एक व्यवस्था insolvency law के अंदर है। चूंकि इसमें multiple lenders हैं और multiple lenders का कई बार कोआर्डिनेशन भी मुश्किल होता है, कोई private sector banks हैं, कोई public sector banks हैं, कोई private creditors हैं, जिनका स्वार्थ कहीं और होगा। यह एक simple, one-line Ordinance है कि RBI को, जो एक fair agency है, उसको अधिकार दिया गया है कि आप इस प्रकार की जो बड़ी कम्पनियां हैं, अगर आपको लगता है कि मौजूदा मैनेजमेंट के साथ इसकी कठिनाई है, तो insolvency proceedings initiate करने के लिए, ये जो multiple bankers हैं, इनको आप direct कर सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस के बाद इसकी urgency यह थी कि the debts are mounting up. हर बार यह विषय आता है, तो हम एक-दूसरे को blame करते हैं। हमारी तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि ये लोन तब दिए गए जब आपकी सरकार थी। अब उसमें सरकार का कोई मंत्री बैठकर लोन तो देता नहीं है। उस समय बैंक्स को commercial consideration को ध्यान में रखकर लगा होगा कि यह expanding sector है और उन्होंने लोन दे दिया। बाद में वह sector sick हो गया और इससे लोन एक प्रकार से बैठ गए। आपकी तरफ से कई बार कहा जाता है कि इनकी संख्या कैसे बढ़ गई। इनकी संख्या इसलिए बढ़ गई कि जो लोन उस वक्त दिए गए, उन पर ब्याज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इसकी गंभीरता को समझते हुए, यह विषय ऐसा है, it is already too late. When Dr. Subbarami Reddy asks as to what is the urgency, the urgency is that it is already too late. The capacity of the banks to lend to small creditors is being impacted. The capacity of the banks to support growth is being impacted.

And, therefore, nobody in this House will want these big people, who have taken such large loans of thousands of crores of rupees, banking on this argument that if they do not pay, where are the takers. अब बैंक मेरा asset ले भी ले, तो क्या करेगा? इसलिए यह बैंक्स की compulsion थी। Insolvency एक ऐसा mechanism है, जिस में आप insolvency proceedings में NCLT के सामने जाओगे, वह 180 दिन के अंदर इस का resolution ढूंढ़ेगा। आप joint venture partner लेकर आओ, आप investment लेकर आओ। आप नहीं लेकर जाओगे तो कोई insolvency professional वहां उसको रन करने के लिए बिठाया जाएगा, आपको बाहर किया जाएगा और फिर asset reconstruction company's fund आज बीसियों की तादाद में इस देश में आ रहे हैं कि we will take over and run the assets. By this process, the banks will slowly start realizing the money. The asset will not be wasted or rusted. The companies will continue to function and the jobs which are

[Shri Arun Jaitley]

there in the companies will also be saved. That is the urgency in the larger interest of the country. It is already a belated measure. Therefore, Sir, I request all sections of the House to kindly support this Bill.

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Both the Resolution and the Bill have been moved for consideration. We will discuss both these together.

Hon. Members, you are aware that at 6.00 p.m., we have a programme to bid farewell to hon. Chairman, and, therefore, we have to complete it by 5.30 p.m. All Members may please try to confine their speeches to five minutes. Now, Shri Basawaraj Patil. You have five minutes.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, before he starts, I just want to draw your attention to one point. I have just noticed it in the proceedings of yesterday, which have been given to me for correction. While we were speaking on the Resolution on 75th anniversary of the Quit India Movement, there was a reference by one hon. Member to Veer Savarkar, which was contested. But, immediately after that, the hon. Member said, * was also *desh bhakt*.' ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can write a letter.

SHRI ANAND SHARMA: No, Sir. He said, * was a *desh bhakt*.' I think, that should be removed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will examine it.

SHRI ANAND SHARMA: That is what I wanted to point out.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Basawaraj Patil, please continue. All speakers may please confine their speech to five minutes. ...(*Interruptions*)... Everybody will take five minutes.

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक): माननीय उपसभापति जी...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, this is a very important Bill. ...(*Interruptions*)... It cannot be discussed in five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do I do? ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, we will start it today and tomorrow we will finish it. ...(*Interruptions*)...

---

*Expunged as ordered by the Chair.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, the Government should not hurry. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Tomorrow, we will finish it. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have no problem but please understand the position. ...(*Interruptions*)... Let me explain. Today, we have fixed 6.00 p.m. as the time for the hon. Chairman's farewell. So, at least, by 5.30 p.m., we should adjourn; otherwise, you cannot reach there, and, we expect all the Members to be there. This is number one.

Secondly, as far as I know, it will not be possible to discuss it tomorrow. Tomorrow, the new Chairman will come. I have got some information that he has shared with me; I can tell you that after he comes at 11.00 a.m. and assumes office, there will be speeches by Members who would like to speak, and, then, he will respond. After that, the House may be adjourned.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Why should it be adjourned? Let this Bill be taken up tomorrow. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Even otherwise, tomorrow, you have Private Members' Business. You cannot take it up. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Since there is urgency in the matter and because the Ordinance is there ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do I do? You tell me.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, I understand that. ...(*Interruptions*)... Since the Ordinance is to be replaced by the Act, therefore, let us start today and conclude tomorrow. ...(*Interruptions*)... Let the morning session be brief. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me be frank with you. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: The morning session may be brief. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sukhendu Sekharji, ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवालः कल नहीं हो सकता है।

श्री सुखेन्दु शेखर रायः कल कैसे नहीं हो सकता है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sukhenduji, you understand my position.

श्री सुखेन्दु शेखर रायः एक घंटा रख दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nareshji, please. ...(*Interruptions*)... Sukhendu ji, you understand my position. You are also Vice-Chairman. Tomorrow, a new Chairman is assuming charge. I cannot take any decision for tomorrow. ...(*Interruptions*)... I cannot take any decision for tomorrow.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: You can convey the sense of the House. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is for tomorrow. You do it. ...(*Interruptions*)... You raise it tomorrow, I have no problem. ...(*Interruptions*)... When the new Chairman comes, ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, you are not retiring. You can convey the sense of the House. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: My request is this.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Let the morning session be for one hour and thereafter the discussion on the Bill can be concluded. Let us start it today. ...(*Interruptions*)...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): दो घंटे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुखेन्दु शेखर राय: दो घंटे कहां होंगे, साढ़े पांच बजे तो खत्म करने वाले हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: फिर तो डेढ़ घंटा है, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आपको किसने मना किया है, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुखेन्दु शेखर राय: यह मामूली चीज नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: हम अपने मेम्बर्स का नाम withdraw कर लेते हैं। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sukhendu Royji, even if it is two hours, your party time is six minutes. I will give you the six minutes. What more do you want? ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: If you say that, then, I am constrained to say that those who do not have even six minutes, they speak for ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not today. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: It happens every day.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not today. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: It happens every day. ...(*Interruptions*).. I can show you this from the record.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But not today. ...(*Interruptions*)... Today, it is not possible. ...(*Interruptions*)... Today, it is not possible to give that kind of time to anybody. You can have all your six minutes. I have no problem. ...(*Interruptions*)... Why are you getting angry? ...(*Interruptions*)... You will have to come to the Chair now. That is the solution. ...(*Interruptions*)... Shri Basawaraj Patil.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): It is usually the Opposition which initiates discussion on the Bill. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is the largest party. ...(*Interruptions*)...

श्री बसावाराज पाटिलः माननीय सभापति जी, the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017. ...(**व्यवधान**)... अभी जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि बैंकों में व्यवहार करते समय बड़ी मात्रा में काम-धन्धा बंद हो रहा है और कई बैंकों के साथ लेन-देन बंद होने पर बड़ी मात्रा में बैंकों में काम रुकने पर आज बैंक बुरी स्थिति में आ गए हैं। हर रोज देश में इसकी चर्चा हो रही है, 6 लाख रुपए का NPA है, 8 लाख रुपए का NPA है, इसलिए सरकार को कोई एक बिल लाना जरूरी था। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने जिन बातों को रखा है, उन्हीं के आधार पर बैंक को विशेष अधिकार देकर, जैसी-जैसी वहां पर परिस्थिति आती है, इस अधिकार के द्वारा, उस विषय को सुलझाना और यदि वे चालू हो सकते हैं, तो उन्हें चालू करना, यदि समाप्त होता है, तो उस दिशा में योग्य निर्णय लेना, सभी बैंकों को इस प्रकार के अधिकार देने की दृष्टि से यह विशेष अमेंडमेंट बिल लाया गया है। आज की परिस्थिति में देश-हित में यह अत्यंत आवश्यक है। मैं इसका समर्थन करते हुए, सभी सदस्यों से इसके समर्थन के लिए विनती करता हूं।

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Thank you, Mr. Deputy Chairman.

Sir, I rise, obviously, to support the Banking Regulation (Amendment) Bill stronlgy and also to use this opportunity to raise a couple of questions to which I hope the hon. Finance Minsiter will respond finally.

Sir, we all know and the hon. Finance Minister has given the background to the urgency for the Ordinance that was issued two-and-a-half months ago which we are converting into a law. There are various estimates floating around. But one of the most authentic estimates that I have read is that the level of NPAs in the system is about rupees nine lakh crore; rupees three lakh crore has been restructured; and another rupees three lakh crore is unrecognised stressed assets. So, we are talking of a total of rupees fifteen lakh crore which could be NPAs, which is roughly equal to the amount of currency that was demonetised and that is ₹ 15.44 lakh crore.

[Shri Jairam Ramesh]

[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair.*]

This is a very significant amount and this is impacting on the financial stability. It is impacting on the banks' ability to lend. In fact, we are faced with a situation where corporate credit is probably running at its lowest level over the past decade and a half and the direct result of that has been high level of NPAs. So, I am one with the hon. Finance Minister that this is an issue that must be tackled at the most urgent basis.

Sir, over the last thirty years, Parliament has passed four laws to deal with this issue. We passed SICA in 1987. We passed the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act in 1993. We passed SARFAESI Act in 2002. And earlier this year we passed the Insolvency and Bankruptcy Code. So, Parliament has passed four laws and the RBI has issued something like six orders or six schemes to deal with this problem of NPAs. Obviously, this has not been very effective and, therefore, the Ordinance had to be issued and the Banking Regulation Act had to be amended.

Sir, one of the reasons that has been given is that in other countries of the world, Central Banks have been given this responsibility. The first question that I would like to ask from the hon. Finance Minister is this. Unlike in other countries, Government is the main owner of the banks in India. The Reserve Bank of India is a regulator. The Reserve Bank of India is a supervisor, the Government is the owner and the owner must have the courage to execute what the Government is now asking the RBI to do. So I would like to ask the hon. Finance Minister: Is the Government shying away from its own responsibility for issuing directives to the banks because of the fear of 3Cs – CBI, CVC and CAG? What is the great merit in transferring this responsibility from the owner, which is the Government, to the regulator and the supervisor, which is the RBI? That is the first question that I would like to ask the hon. Finance Minister because unlike in other countries, the Government owns the banks in this country and, in my view, saddling the regulator and the supervisor with this backseat-driving role *vis-à-vis* the banks introduces huge conflicts of interest and also dilutes the responsibility of the owner.

Sir, my second question is this. Even after the recognition of all the stressed assets, even after all the directives have been issued by the RBI – and already 12 assets have been identified where outstanding exceeds ₹ 5,000 crore; one of them has taken the Government to court, but that is a separate issue; Insolvency and Bankruptcy Code has already been invoked in 12 cases and I welcome that step. However, my question is this. Even after doing all this, there will be a need for recapitalisation of banks. Sir, the best estimate that I have been able to collect from those who

are in the know is that the Indian public sector banks will, over a couple of years, require 26 billion dollars for meeting Basel-III capital adequacy norms. As opposed to the requirement of 26 billion dollars, the Government has committed only three billion dollars for recapitalisation. So, my second question to the hon. Minister is: How does he propose to fill the gap between the recapitalisation requirements, which is 26 billion dollars, and the commitment that he has made, which is three billion dollars? Is he expecting banks to go to the market to raise money? Is he going to privatise some of these banks? What is the Government's strategy for meeting the full recapitalisation requirements as per the Basel-III adequacy norms?

Sir, my third question is a larger question. It relates to the current economic situation which in many parts is caused by the sluggish growth in bank credit to industry. Sir, there is no doubt that over the last couple of years, the economy has been somewhat sluggish; somewhat sluggish largely because of the reluctance of banks to lend for a variety of reasons. There are other indicators which show sluggishness of the economy. In spite of an impressive record in the generation of electricity, electricity consumption has not increased very significantly; rail freight has not increased very significantly; cement consumption is not increasing; sale of commercial vehicles is not increasing. Therefore, there is an ample evidence to suggest that the economy is not exactly in a buoyant mood. Sir, a day before yesterday, the Finance Minister answered a question. I mean Question Hour did not take place but in the Starred Question, the hon. Finance Minister replied that the total expenditure of the Union Government during the first quarter of this year was ₹ 6,50,730 crore, which is 30 per cent of the Budget Estimate as opposed to about 26 per cent in the previous year. Sir, I welcome this because, what has happened is, by advancing the date of the Budget you have frontloaded the expenditure in the first quarter and this is something to be welcomed. However, what these numbers suggest is that in the first quarter of 2017-18, the Government has already consumed 81 per cent of the budgeted fiscal deficit. This is an extraordinary situation. Historically, we have been averaging about 55 per cent to 60 per cent of the fiscal deficit in the first quarter. But, suddenly, we are confronted with a situation where in the first quarter of this year, we seem to have reached a level of over 80 per cent which means that if this is true, in the months to come, in the balance of the fiscal year, expenditure will not increase to the extent that is being desired. Because Government expenditure is really the driver of economic growth, because private investment is not picking up, because private investment is at a historic low, the Government is running, as has been said, on a single engine, the engine of Government spending, Government investment. This is very important to understand from the Finance Minister whether, in fact, in the first quarter of this year, he has already reached a very dangerous level of fiscal deficit which will circumscribe his expenditure options later on.

[Shri Jairam Ramesh]

Sir, finally, I want to say that there is a tendency in this country to look at NPAs as these are all crooks. NPAs arise because of a variety of reasons. Some people are willful defaulters. They should be punished. They should be put behind the bars. The law must be applied without fear or favour. But market conditions change. International markets change, domestic markets change. Competition happens. So, to assume that everybody who has an NPA has done something suspicious, I think, is going to be a very wrong mentality. It will send a wrong signal to entrepreneurs and, therefore, I would like to request the hon. Finance Minister that in the case of the NPAs, there should be some documentation put on into the public domain as to why, in fact, these NPAs ended up being what they are. Was it market conditions? Was it competition? Was it actually some willful decision that was taken by the enterprises or was it a case of over-leveraging? I think, this is very important because we need to send signals to industry that investment is not a bad thing. Sometimes investment may work out, sometimes investment may not work out, for which we have now passed the Insolvency and Bankruptcy Code.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. Thank you.

SHRI JAIRAM RAMESH: So, in short, Sir, I support the Amendment. I think the Amendment was needed. It was urgently needed. I hope that the Amendment will lead to a faster recovery of outstandings. But I also hope that in the process, we have not saddled the regulator and the supervisor with another function of backseat driving, second guessing the boards of commercial banks and in the process the Government of India is abdicating its role as the owner of the public sector banks. Thank you, Sir.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस बिल का तो मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन माननीय मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूँ क्योंकि बैंकों को हम लोगों ने बहुत से अधिकार दिए, कई बिल पास किए, तो यह आखिरी बिल अधिकार का होना चाहिए। इसके बाद यह नहीं होना चाहिए कि बैंकों को अभी और भी कोई अधिकार देने हैं। हम उनको इतने अधिकार देते चले आ रहे हैं और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि आप उद्योगपतियों को तो ठीक मान रहे हैं कि वे बैंक का पैसा ले गए, लेकिन उसमें आपके कितने सीएमडी, कितने मैनेजर मिले हुए हैं, जिन्होंने उन लोगों को इतना पैसा दे दिया, जितनी उनकी हैसियत नहीं थी? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम 13 परसेंट एनपीए पर चले गए, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा एनपीए में चला गया। आज बैंकों के सामने स्थिति इतनी खराब है कि प्रति वर्ष आप बजट से बैंकों को 20 हजार करोड़ रुपए देते हैं। इसके बाद भी जो बैंकों की स्थिति खराब हो रही है, उसे आप संभालिए। मैं इस बात का बिल्कुल विरोधी हूँ कि आप

economic affairs में जितने भी एक्ट्स बना रहे हैं, उनमें आप जेल जाने का प्रावधान कर रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ।

प्रजातंत्र के चार खम्भे माने गए हैं — हम लोग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। लेकिन आज आपकी सरकार ने खम्भे बदल दिए हैं। अब ये हो गए हैं — ED, CBI, Income Tax और PMLA. देखिए माननीय मंत्री जी, मैं criticize नहीं कर रहा हूँ। आज इतना slump है, आपकी नोटबंदी के बाद तो इतना बुरा असर हुआ है कि इसके बाद इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल हो गया है। सबसे ज्यादा पैसा चार सेक्टर्स में लगा हुआ था। उनमें से एक स्टील है। आपने स्टील वालों को राहत दी। चलिए, पता नहीं, वे लोग बराबरी पर आए कि नहीं, लेकिन आपने स्टील वालों को कुछ राहत दी। इसके बाद आपकी पॉवर इंडस्ट्री है। पॉवर सेक्टर में जितने प्लांट्स लग रहे हैं, उनके सामने प्रॉब्लम यह है कि पॉवर का कोई खरीदार नहीं है। पीयूष जी हर जगह कहते हैं कि हमारे पास surplus है, लेकिन राज्य उसे कैसे खरीदेगा, जब राज्यों के पास पैसा ही नहीं है। राज्यों के विद्युत परिषदों ने बैंकों से इतना लोन ले लिया कि वे सारे घाटे में चल रहे हैं। कौन सा ऐसा राज्य है, जिसका विद्युत परिषद बहुत अधिक घाटे में नहीं है? सबने सरकार की गारंटी पर लोन ले लिया। विद्युत परिषद की उसे चुकाने की स्थिति नहीं है। यह भी आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। रीयल इस्टेट में कितना पैसा लगा है! हम लोग रोज पढ़ते हैं। जब RERA बन रहा था, अब तो हमारे चेयरमैन हो गए, मैं उस समय भी कह रहा था कि आप RERA के माध्यम से इस पर रोक लगाइए। ठीक है, आप रोक लगाइए, जो लोग रीयल इस्टेट के नाम पर लूट कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन आज रीयल इस्टेट का सेक्टर बंद होने के बाद इतनी बुरी स्थिति है कि 12 करोड़ लोग सिर्फ रीयल इस्टेट बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं। हम चीन से competition कर रहे हैं। चीन में 2 परसेंट ब्याज पर लोन और 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली है। वहां लेबर सस्ता है और लेबर के लिए यह fix है कि उसको इतना काम करना पड़ेगा। यहां तो लेबरर्स लाल झंडा लेकर निकल पड़ते हैं और काम ही नहीं करते। जब हम उस चीन से competition करेंगे और हम 14-15 परसेंट ब्याज देंगे, अगर हम उस ब्याज को ठीक तरीके से नहीं वसूलेंगे, तो काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप उसे वापस लीजिए, इसके लिए बिल पास कर दीजिए, लेकिन जो उद्योगपति इसे देना चाहते हैं, एक बार आप उनके लिए इसे reschedule कर दीजिए, दूसरी बार OTS का chance दीजिए और तीसरी बार कस कर वसूली कीजिए, हम लोग मना नहीं करते हैं। लेकिन मुझे दुख है कि ऐसा कौन सा बैंक का मैनेजर या CMD है, जो रुपया लिए बिना कर्ज दे रहा है। तमाम लोग पकड़े भी गए हैं, CBI ने भी पकड़ा है। आज आप तमाम CMD के बट्टे-खाते तो देख लीजिए कि कितना है। रिजर्व बैंक यह नहीं बताता कि नोटबंदी के बाद कितने नोट आए। वे गिन ही नहीं पा रहे हैं। हमारे हरदोई में एक बैंक मैनेजर ने हमसे कहा कि अभी तो रुपए हमारे पास रखे हैं, रिजर्व बैंक नहीं गए हैं। रिजर्व बैंक इनको कब तक गिनेगा? मैं तो कहूँगा कि आज आप ही घोषणा कर दीजिए, आप ही बता दीजिए, आरबीआई नहीं बता पाया है। हम लोगों ने एक दिन फाइनांस कमिटी में उनसे पूछा कि आप बता दीजिए कि अभी तक आपके पास कितना रुपया आया है, तो वे बता ही नहीं पा रहे थे।

राज्यों ने कर्ज माफी की घोषणा करनी शुरू कर दी है। क्या कर्ज माफी किसानों की समस्या का समाधान है? आपने तो खुद ही कहा था कि केंद्र सरकार कर्ज माफी के पक्ष में नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा कर दी। आज तक G.O. जारी नहीं हुआ

[श्री नरेश अग्रवाल]

है। मुझे पता है कि G.O. इसलिए लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें बाबू लोगों ने इतने प्रावधान कर दिए हैं कि वह G.O. जारी होने के बाद किसी को कर्ज मिलेगा ही नहीं। जो फसल बीमा योजना थी, आपने प्राइवेट कंपनी को दे दी। उनको फसल बीमा का जितना रुपया मिलता है, उसमें से केवल 20 परसेंट किसानों को मिल रहा है, 80 परसेंट रुपया उन प्राइवेट कंपनियों को मिल रहा है। उसमें कौन लोग हैं? मंत्री जी, मैं तो आपसे पूछना चाहूँगा कि वे कौन सी प्राइवेट कंपनियां है, वे प्राइवेट कंपनियां किन बड़े उद्योगपतियों की हैं, जिनको सरकार ने फसल ऋण बीमा दिया है? अगर आप बता देंगे, तो यह सबके सामने आ जाएगा कि आखिर कौन-कौन लोग हैं। एक-एक बीमा कंपनी को साल में दो-दो हजार करोड़ रुपए बच रहे हैं। किसान को क्या मिल रहा है? किसान तो भुखमरी में चला गया और आत्महत्या कर रहा है। हमारी सरकार की कोई नीति नहीं है। हम लोग रोज़ कहते हैं कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहां मिलता है? कल ही अखबारों में निकला था कि उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आलू का कोई खरीददार है ही नहीं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि हम आलू खरीदेंगे — प्रोफेसर साहब ज्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि ये तो आलू के क्षेत्र में रहते हैं। फरुख़ाबाद से आलू शुरू हो जाता है और आगरा तक आलू है। आज किसान की हालत यह है कि किसान आलू निकाल नहीं सकता, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज को वह जितना पैसा देगा, उतने रुपये में उसका आलू नहीं बिकेगा। आप कलराज जी को भेज दीजिए, एक दिन ज़रा ये वहां पर चले जाएं और वहां जाकर आपको रिपोर्ट दे दें। ये तो सही रिपोर्ट देंगे, क्योंकि... मैं आगे नहीं कहूंगा। मेरा आपसे यह कहना है कि अब अगर आप बैंक ऐक्ट बनाइए तो माल्या जैसे लोगों को भागने का मौका भी मत दीजिए। बैंक ऐक्ट में आप कंडीशन डाल दीजिए कि जो विदेश भाग जाएंगे... अब आपके पास विदेश में तमाम जगह से संधि नहीं हुई है। अभी शायद स्विटज़रलैंड ने आपसे संधि की है और वह नाम देने को तैयार हुआ है, वह भी अभी दो साल में नाम देगा, लेकिन तब तक वहां का सब रुपया निकल चुका होगा। फिर रह क्या गया?

पनामा के लिए हम लोगों ने इतनी बार आपसे कहा। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री पनामा के केस में हटाए जा सकते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में पनामा के केस में सब नाम ओपन हो गए हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ। फेसबुक पर विनोद दुआ की तमाम न्यूज़ चलती रहती है, उन्होंने एक-एक नाम की घोषणा कर दी है, आप कहिए तो हम वह पूरी लिस्ट पढ़ दें, जिसकी उन्होंने घोषणा की है। वह लिस्ट सही है या गलत है, इसको तो आप देखेंगे। पनामा पर ऐक्शन क्यों नहीं हुआ? जिन लोगों ने पनामा में कंपनी बनाई, ब्लैक मनी भेजी, पनामा में उसको व्हाइट किया और एफडीआई के माध्यम से हिन्दुस्तान ले आए। आखिर क्यों? 10% पर उन्होंने अपना सारा पैसा व्हाइट कर लिया, आप भी खुश हो गए कि हमें इतना एफडीआई मिल गया, क्योंकि विदेश से एफडीआई आ गया और वही पैसा हिन्दुस्तान में व्हाइट मनी के रूप में आ गया। आप उन लोगों पर भी कार्यवाही करिए।

रिज़र्व बैंक ने हमको आंकड़ा दिया कि 12 उद्योगपति ऐसे हैं, जिनके ऊपर टोटल एनपीए का 25 प्रतिशत है। आप भी उस दिन बोल रहे थे कि 12 उद्योगपति ऐसे हैं, जिनके ऊपर, बैंक का जितना टोटल एनपीए है, उसका 25 प्रतिशत है। आप उन 12 उद्योगपतियों के नामों की घोषणा क्यों नहीं कर देते? किसान पर तो कभी 1 लाख रुपये का कर्ज भी हो जाए, तो मालूम पड़ता

है कि उसको रात में तहसील में बंद कर दिया जाता है, बोर्ड पर नाम भी लिख दिया जाता है। आपने Bank Secrecy Act बना दिया, हम कहते हैं कि उस ऐक्ट को भी अब आप खत्म करिए। जब सुधार ही लाना है, हर चीज़ को ओपन करना है, तो हर चीज़ ओपन हो जाए।

मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर आपने किसान को लोन बहुत सस्ता नहीं दिया, तो इस देश में किसान उन्नति नहीं कर पाएगा। वैसे भी जोत छोटी होती चली जा रही है। जोत अगर छोटी होती चली जाएगी, तो किसान को क्या लाभ मिलेगा? मैं चाहता हूं कि बैंक सिर्फ बड़े लोगों के लिए न रहें। गांव में बैंक ही नहीं हैं, इसी मारे तो Ponzi scheme चल रही है। ...**(समय की घंटी)**... मालूम पड़ा है कि अब भी एक लाख की आबादी पर मुश्किल से एक बैंक है। तमाम ऐसे इंटीरियर गांव हैं, जहां बैंक हैं ही नहीं, वे लोग अपना पैसा कहां जमा करें?

अब स्टेट बैंक ने यह किया है कि जो अपने सेंविग एकाउंट में एक करोड़ रुपये से कम पैसा जमा करेगा, उसकी ब्याज दर घटा दी जाएगी और जिसके एकाउंट में एक करोड़ रुपये से ऊपर होगा, उसकी ब्याज दर सामान्य रखी जाएगी। आप आज ही यह घोषणा करिए, एक करोड़ रुपये से नीचे वालों की ब्याज दर ज्यादा होनी चाहिए और एक करोड़ से ऊपर वालों की ब्याज दर कम होनी चाहिए। आप ऐसा करेंगे, तब तो लगेगा कि सरकार किसानों के हित में कुछ काम कर रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): नरेश जी, समाप्त कीजिए, अभी और लोग भी हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, मैं तो समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपसभाध्यक्ष: नहीं, समय कम है और फेयरवेल भी है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश में unemployment बढ़ रही है, किसानों की बुरी स्थिति है। कर्जा माफी का जो चैप्टर है, इससे तो किसान की कर्जा चुकाने की नीयत ही खराब हो गई है। वह कहता है कि लोन ले लो, कभी न कभी कोई सरकार आएगी और कर्ज माफ कर देगी। इसके कारण अभी तक जो बैंक कर्जा देते थे, उन्होंने भी देना बंद कर दिया है। बैंकों का nationalization गरीबों के लिए हुआ था, तो आप ऐसी स्कीम बनाइए, जिससे उन गरीबों को फायदा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके बिल का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद अब बैंकों को कहने का बहाना नहीं मिलेगा कि हम एनपीए नहीं वसूल कर पा रहे हैं।

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (Puducherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017. The Bill proposes to give more powers to the Reserve Bank of India to deal with the large accumulated Non-Performing Assets. It works out to ₹ 9.64 lakh crores as of December, 2016. Another ₹ 2.0 lakh crores have been added during the first quarter of 2017.

According to the RBI, the corporate sectors alone accounts for 88 per cent of the NPAs. The RBI data shows that 40-50 defaulters alone account for 70 per cent of the cases, contributing to the stressed assets. The Banks may have to take

[Shri N. Gokulakrishnan]

a haircut of 60 per cent, worth ₹ 2.4 lakh crore, to settle 50 large stressed assets with debt of ₹ 4 lakh crore. Indian Banks need to provide, at least, ₹ 18,000 crore additionally towards the 12 accounts identified by the RBI for reference to the National Company Law Tribunal under the Insolvency and Bankruptcy Code in the financial year of 2018.

The banks have written off a total of ₹ 2.46 lakh crore worth of loans in the last five years and this might have benefited a few people, but the waiving of agricultural loans surely benefits millions and millions of poor farmers and prevents suicides by them. Therefore, the Centre should bear the entire burden of farmers' loan waiver scheme instead of putting the burden on the State Governments.

Sir, I would like to mention here one thing that the farm loans account for only one per cent of bad debts. However, there is a tendency to blame the loan waivers in the farm sectors. Being an agricultural economy, we can't blame farm loan waiver scheme alone for the erosion of 'honest credit culture'.

In several cases, factors operating at the global level, determine the local trade trends. Take the steel sector, for example, it accounts for 25 per cent of the corporate bad debts. But starting from 2010 till December, 2016, the Government of India allowed the free inflow of foreign steel products from Korea, Japan, China, etc., which offered low prices. The local manufacturers, who availed huge loans besides large investments, could not compete with them. The Government of India also did not come to their rescue through an effective EXIM Policy at that time. Consequently, they suffered heavy losses and ultimately they were pushed into the debt trap. This was the major reason for the huge default by this sector.

More important is the laxity in the credit risk appraisal and loan-monitoring by the banks. For example, in the case of MSME sector, stringent collateral security is demanded. But I do not know whether such credit risk appraisal norms are enforced for the corporate sector as in the case of the MSME sector. Even in the field of loan recovery, it is astonishing that so much concession and tolerance is shown towards the big players while the MSME, small and marginal farmers are being harassed.

Sir, in retrospect, the troubled accounts fall into three categories: (1) Genuine and circumstantial defaulters; (2) Wilful defaulters and (3) Habitual offenders. The genuine and circumstantial borrowers are unable to repay loans due to the downturn of the industry, largely conditioned by the global economic trends. Such people can be given time to perform provided their projects are viable, business models are robust and the chances of recovery are bright. But in the case of the wilful defaulters, the

institutional interventions like Joint Lenders Forum, Corporate Debt Restructuring, Strategic Debt Restructuring and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets are already in operation. The performance of the Asset Reconstruction Companies, which are mostly in the private sector, and which deal with NPAs, is not satisfactory. While appreciating the current set of well-calibrated policy initiatives for resolution of stressed assets, the onus is now shifting towards the RBI in the recovery process. On the one hand, the borrowers would have to modify their priorities towards regular repayment of loans if they want to stay in the business and, on the other, the Bill offers great relief and freedom for bank managements also.

Hon. Vice-Chairman, Sir, in conclusion, the amended package empowers the RBI in regulating the process of resolving the stressed assets as well as the way of dealing with defaulters. The bad loan scenario in the country is certainly grim. Therefore, the resolve of the Government for tackling this problem through this Bill is a big boost to the Indian economy in general and to the banking sector, in particular.

Without a strong and healthy banking system, it is difficult for a developing country like India to become an economic super power. But, at the same time, without a time-bound, effective and fool-proof recovery system, it is doomsday for the sustainability of the banking sector. Now, with the passage of this Bill, it becomes the responsibility of the Reserve Bank, the public and private sector banks and the high profile borrowers to work in tandem and make it successful.

With this, I conclude and support the Bill. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Shri Sukhendu Sekhar Roy.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, at the outset, I would like to place on record my dissent regarding the way in which this Bill is being considered today and the way it would, possibly, be passed. Every day, in the media, there are reports that Parliamentarians are not serious as they do not want to discuss Bills, etc. But we do want to discuss all these things. The Parliament is meant essentially for legislation. It is not meant for organising functions, ceremonies, etc.

So, at the outset, I would like to speak about the Bill. First of all, the objective of the Bill is mentioned here in one line, which says, "It seeks to authorise the Reserve Bank of India to issue directions to any banking company or banking companies to effectively use the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code for timely resolution of stressed assets." Here, I have a doubt whether at all there would be time-bound results after the imposition of this Code.

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

It is true that NPAs have grown alarmingly in the recent years. As per the estimates in March, 2017, the Gross Operating Profit of 21 Public Sector Banks, taken together, was ₹ 1,50,240 crores. But the net profit was only ₹ 574 crores. As against all these figures, the gross NPAs of these Public Sector Banks are worth ₹ 6,05,991 crores. This is very alarming. There is no doubt about it. But the question is whether there would be any impact of the Insolvency and Bankruptcy Code so far the achievement of results in a time-bound manner are concerned. I am constrained to say that this objective cannot be achieved because – I cannot go through the provisions of this Bill in detail due to the paucity of time, but – the Bill has, essentially, left enormous scope for more and more un-ending litigation. I will give you one example. Recently, the Government had advised the RBI to initiate proceedings under the Insolvency and Bankruptcy Code against 12 defaulting account holders. One of these defaulting account holders managed to get stay from the High Court. All the proceedings have been stayed. Now, for years together, this would continue in respect of each and every big fish who have eaten away the public money through the public sector banks.

Sir, there are 550 large NPA accounts, not twelve. Nareshji mentioned twelve; they may be just 25 per cent of the total NPA. This is according to the estimates of the RBI, which appeared in various newspapers. Hence, according to me, the proposed Amendments would only help the big fish who have eaten away the public money rather than the recovery of the assets of the people of India.

I go to my last para on the RBI guidelines. Criminal proceedings can be initiated against the wilful defaulters. There are circulars. In the master circular of the RBI, there are a number of circulars whereby the RBI has directed the banks to initiate criminal proceedings. I would request, through you, Sir, that the hon. Finance Minister should inform this House how many criminal proceedings have been initiated against the big fish so far. The House wants to know this. He is also on record saying, the hon. Finance Minister is on record saying that criminal proceedings will be drawn against those who have made a fraud and those have siphoned off the money, the loan amount. Sir, if at all any criminal proceedings have been initiated, how much amount has been involved and why is the Government shying away from naming those people? The Government has pleaded before the apex court that, please for God's sake, don't disclose the identities of those persons. Why this double standard? When Government can place this amendment before the House, why has not the Government initiated any move to amend the archived RBI Act of 1931 and the archived Banking Regulation Act of 1949 whereby some draconian provisions have

been made debarring the RBI, debarring the banks from disclosing or parting with any commercial information? The time has come that the Government must take a move to amend those archival provisions, those draconian provisions of the archived Acts. This is my demand before this Government, through you, Sir. Now, I am giving you another example that not only twelve that the RBI did not name, the media has speculated about 15 to 16 names and they are Essar, Bhushan, Lanco, Videocon, Punj Lloyd, Electrosteel, Aban Holdings, ABJ Shipyards, Monnet Ispat and several other notorious names are there. One of them has run away. It is not Mallya. There is another gentleman, who has run away from this country and he has taken the citizenship of St. Kitts and with St. Kitts India does not have an extradition treaty. If the Government of India at all wishes, it cannot bring him back to this country and produce him before the court. So, this is what is happening. This is why I say that this amendment will do nothing. It will come with a big zero result and that is why I oppose this Bill in its entirety. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have finished before time.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Yes, Sir. I am always afraid of the Deputy Chairman. I was apprehending that he may be coming any moment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you.

श्री हरिवंश (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अंदरूनी हालत खराब है, उसकी सेहत ठीक करने के लिए यह जरूरी, कारगर और प्रभावी बिल है, इसलिए मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह इस रूप में प्रभावी होगा, जैसे टैक्स, खास तौर से इनकम टैक्स देने वालों की संख्या इस देश में कितनी कम थी, पिछले दो-तीन वर्षों में demonetisation से लेकर जो अनेक कदम उठाए गए हैं, उनका जो असर हुआ, उसके बारे में आज के अखबार में खबर है, "टैक्स देने वालों की संख्या 25 परसेंट बढ़ी है और इससे सरकार की आय बढ़ी है।" आपने पिछले तीन वर्षों में बैंकों की सेहत ठीक करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनको मैं आपको गिनाता, पर समय का अभाव है, उससे यह जो एनपीए की खराब होती स्थिति है, इस पर भी पाबंदी होगी।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल की और इसके समर्थन की जरूरत क्यों है? पिछले पांच वर्षों के फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्स से जो आंकड़ें हैं, उनके अनुसार मैं कह रहा हूँ। 2012-13 से 2016-17 के बीच 2.46 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ हुए हैं और टोटल स्ट्रेस्ड एसेट्स, जो दिसंबर, 2016 में लोक सभा में सूचना दी गई, उसके अनुसार 9.64 लाख करोड़ हैं। अखबारों में 8 लाख करोड़ रुपए की एनपीए की सूचना है और खुद केंद्र सरकार का 2015 में जो estimation था, उसके अनुसार 2015-16 से 2018-19 के बीच पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फाइनैंस करने के लिए, ताकि वह इस तरह की चीजों से निपट सके, 1,80,000 करोड़ रुपए के फंड की जरूरत बताई गई। अब इसमें अपेक्षा की गई थी कि 70,000 करोड़ रुपए सरकार

[श्री हरिवंश]

देगी और बैंकों को 1,10,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करना पड़ेगा। पर, खुद भारत सरकार की रिपोर्ट – इकनॉमिक सर्वे, 2016-17 – कहती है कि यह अमाउंट कम है, इसमें और कैपिटल इनफ्यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। इस रूप में यह स्थिति गंभीर है। अब इसके दो मुख्य कारण हम सब सामान्य लोगों की नजर में दिखाई देते हैं। पहला genuine कारण, genuine कारणों के तहत, जैसा वित्त मंत्री जी ने बताया, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम आई हैं या 2003 से 2008 के बीच जो boom period था, वह अब नहीं है। यह सही और genuine कारण है, जैसा अभी जयराम रमेश जी ने भी बताया, परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण मैं मानता हूं कि हमारे यहां ऐसे मामलों में कानून का भय कम हो गया है। दिसम्बर, 2016 तक Public Sector Banks में 9,130 wilful defaulters identify किए गए थे, जिन पर कुल बकाया यानि total outstanding 91,155 करोड़ रुपए था। इसलिए हमारी पहली जरूरत होनी चाहिए कि सभी wilful defaulters में कानून का भय हो। अब मैं दूसरा सुझाव देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

महाभारत में एक मशहूर प्रसंग आता है — 'महाजनो येन गताः सो पंथा', जिसका अर्थ है कि ऊपर कुर्सी पर बैठे लोगों का आचरण कैसा हो, कामकाज कैसा हो, क्योंकि उसका असर उस संस्था पर नीचे तक पड़ता है। देश में पिछले कुछ वर्षों से Public Sector Banks में जिस तरह से बड़े पदों पर नियुक्तियां होती रहीं हैं, आज उस मानक को, उस तरीके को बदलने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि Syndicate Bank के एक चेयरमैन घूस लेते पकड़े गए। एक Indian Overseas Bank है, जो आज बहुत खराब हालत में है। उसके एक चेयरमैन के बारे में पता चला कि other considerations के कारण वह बैंक के Chairman and Managing Director बने। उन्होंने अपने समय में बड़े accounts में जितने advances दिए, उनमें से 70 परसेंट बाद में NPA बन गए। इसी तरह एक IDBI बैंक है, जो एक समय देश का prestigious institution माना जाता था, फख्र करने योग्य बैंक था। उसके चेयरमैन पर आरोप लगा। उन्होंने अपने समय में जिस तरह लोन दिए, उसी का परिणाम है कि आज 44,753 करोड़ रुपए उस बैंक का NPA है, जो कुल लोन का एक-चौथाई बनता है। इस बैंक के जिस चेयरमैन का मैं उल्लेख कर रहा हूं, उन्होंने ही Kingfisher को लोन दिया। आज Kingfisher की क्या हालत है, उसे हम सब जानते हैं। उसके owner आज विदेश में हैं और उनका बेंगलुरू में जो घर बन रहा है, उस पर helicopter उतार सकें, उसकी व्यवस्था हो रही है। ऐसी स्थिति में इन सबको कानून का भय होना जरूरी है।

अंतिम बात मैं कहता हूं कि भारतीय बैंकों में और खास तौर से, सरकारी बैंकों में, इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1975-76 में इस देश के State Bank of India में बड़ी कम उम्र में एक चेयरमैन हुए — आर. के. तलवार साहब, जिन्होंने बड़ा उल्लेखनीय काम किया। उस समय आर. के. तलवार साहब पर दबाव डाला गया कि किस तरह particularly एक खास पार्टी को लोन देना है और वह दबाव तत्कालीन सत्ता के राजकुमार के द्वारा डाला गया, जो किसी संवैधानिक पद पर न रहते हुए भी उस समय सबसे बड़ी हस्ती थे। उन्होंने कहा कि हमारे बैंक की शाखा इसे evaluate करेगी और अगर financial रूल्स के मुताबिक ठीक होगा, bankable project होगा, तो हम finance करेंगे। ...(**समय की घंटी**)... मैं बस एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। बाद में बैंक के मैनेजर ने कहा कि इस कंपनी को finance करना viable नहीं है और लोन नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि

Mr. N. Vagul, जो इस देश के जाने-माने Banking Expert रहे हैं, जो स्वयं कई बैंकों के चेयरमैन रहे, आज जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, जो Bank of India के चेयरमैन भी रहे, ICICI बैंक के चेयरमैन भी रहे, उन्होंने आर. के. तलवार साहब के बारे में एक किताब लिखी है, जिसमें इसका उल्लेख किया है। अंततः he was forced to quit. अगर हम बड़े पदों पर बैठे लोगों को autonomy नहीं देंगे, ईमानदार लोगों को नहीं रखेंगे, तो ऐसे ही हालात होंगे, जो आज हो रहा है और हमारा NPA लगातार बढ़ता जाएगा। इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह होगा कि बैंको के Chairman and Managing Director दोनों पदों को अलग किया जाए और पिछले 5-10 वर्षों में इन पदों पर रहते हुए, जिनके कार्यकाल में सबसे अधिक NPA हुए, जिनके समय में सबसे ज्यादा willful defaulters हुए, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि भविष्य के लिए सबक मिले। समय देने के लिए धन्यवाद।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): I thank you Mr. Vice-Chairman, Sir. I crave your indulgence for time as I have many things to say on this Bill. Before passing this Bill, the House and the Government must taken note of my points. So, I crave your indulgence.

Sir, basically, this Bill is empowering the RBI to give direction to banks to invoke the Insolvency and Bankruptcy Code against the loan defaulters. The 'loan defaulters', to begin with, has been given a respectable name called 'Non-Performing Assets.' And, thereafter, it has been given the name of 'Stressed Assets.' After that, it has been given the name of 'Non-cooperative Borrowers.'

Sir, those who are pilfering banks' money in the name of investment are given a respectable name! This is all tax-payers money. And, you are giving them a respectable name!

Secondly, the CEO of the NITI Aayog is uttering, day-in-and-day-out, in the media that everything should be privatized. In this context, I wanted to know whether you are taking any action against banks. It is fraught with many apprehensions as to what your real intention is. This apprehension has further been substantiated by a similar utterance by the Deputy Governor of the RBI by giving a clarion call that banks should be re-privatized! In this background, I think, before passing this Bill, it is the duty of the Government to clear and clarify these apprehensions.

Sir, the Bill empowers banks, through the RBI, to invoke action against defaulters. It is a welcome step. Sir, I have an occasion to agree to the statement made by the hon. Finance Minister that, yes; it is already late and we are taking action. The issue of mounting NPAs has consistently been talked about in this House and we have been demanding action against defaulters. Now, the hon. Minister is saying that the Government is late in taking action. So, the Bill should be passed. I agree that this Bill should be passed. And, I also agree that you are late in taking action. But, the

[Shri Tapan Kumar Sen]

context in which you are taking action is raising apprehension. You have already, through the RBI, made a public statement that banks should go in for a 'haircut' to address the NPAs. What is 'haircut?' It means, writing-off loans. Already, Sir, a good amount has been written-off. Whose money is this? It is people's money in banks. How do you write-off? A good amount has been written-off. Sir, some ₹ 3 lakh crores has been written off! And, your Deputy Governor of the RBI is promoting the idea of a hair-cut! Then, you brought another Bill — it is in the process of preparation — called Financial Resolution and Deposit Insurance Bill. It is being conceived with sweeping arbitrary powers to a resolution board constituted under this Bill to liquidate banks. So, the FRDI Bill is being brought and structured to liquidate banks which are under loss! And, at the same time, the Deputy Governor of the RBI talks everyday that everything should be re-privatized. And, at the same time, you are suggesting for a haircut! It means, give away loans at a time when many people are involved in that.

So, in this background, how this action is going to be effective has to be seen. To keep it non-effective, you are intentionally empowering banks, through the RBI, to recover loans under the Insolvency and Bankruptcy Code in a manner so that banks need not be held accountable. Why is RBI in between? It is banks which are suffering from loan defaults. Some people took money and are not paying back. It is banks which are suffering from loan defaults. If they have to recover money, they are being given an instrument; fine. It is welcome. Now, for application of that instrument and to see whether banks are properly applying that instrument, how do you held banks accountable if they are to act as per the direction of the RBI? What is the attitude and approach? Sir, names of only 12 companies came in the public domain against whom action is proposed to be taken! What is the amount involved? It is ₹ 2.53 lakh crores. It is less than 25 per cent of the total estimated NPAs. The Government is also agreeing to this figure. It is hardly 25 per cent. Sir, it has been talked about a number of times by the Government that 80 per cent of NPAs are due from just 50 companies. These 50 companies cannot be straightened. The sovereign Government of India is having sovereign powers, but they cannot take an appropriate action against 50 companies. Only against 50 borrowers! And, who are they? They are accompanying the Ministers in their foreign trips. And, these foreign trips are facilitating business-contracts with those private companies in Israel and other countries. ...(*Time-bell rings*)... Please allow me to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I am just reminding you that we have time constraint.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Okay; okay. Sir, I am trying to be as brief as possible.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please be brief.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: So, these apprehensions must be cleared by the Government. Privatization cannot be a solution. I would like to draw the attention of the House and also that of the Government to another fact that besides the banking system many other public sector companies are being targetted for privatization. Hon. Minister says that the power sector is also suffering because of the NPAs. Hon. Steel Minister is sitting here. Please note that the steel sector is facing a severe crisis. But, none of the public sector steel company has defaulted in their obligation to service the loan taken from the banks. Hon. Minister should confirm this. The SAIL is bleeding after a loss of ₹ 4,000 crores. But, they have not defaulted on their obligation of debt servicing to the banks.

You are targetting to privatize the Air India. Yes, they are in severe soup. But, even then, they have not defaulted even for a single day in repaying their loans to the banks. But, you are targetting them for wholesale privatization. Today, you are empowering the banks to invoke the Insolvency and Bankruptcy Code on the companies who have taken loans. Tomorrow, the FRDI Bill empower the Government to invoke the Insolvency and Bankruptcy Code on the banking companies also, including the nationalized banks. What is your plan? What is your programme? That raises a doubt. That raises apprehensions. That creates the problem of credibility. I welcome the steps to empower the banks. But, my suggestion is, please take out the RBI from the picture. The RBI is a regulator. They are not service providers. It is a Government-owned bank. The Government must direct and the banks should be directly empowered to invoke the Insolvency and Bankruptcy Code. And, if they don't invoke, their Boards can be held accountable. A quick recovery is possible only through this process. In between, you keep another agency, which is loaded with different ideas. If being targetted to be privatized, even this project will not meet even the minimum success. I can tell you this in advance. That is, at least, my understanding.

So, my suggestion is – accordingly, my colleague. Shri T. K. Rangarajan has moved certain amendments also – that they should directly be empowered and the role of the Reserve Bank of India is to supervise, to regulate, but not to direct. They cannot select the companies. The responsibility of selecting the companies against whom the Insolvency and Bankruptcy Code is to be invoked has to be discharged by the Board of Directors of the bank. Only then, the accountability can be established and the process can be expedited. Otherwise, it is not possible. Otherwise, it will

[Shri Tapan Kumar Sen]

5.00 P.M.

only be 12 companies. Rest of the 38 companies will be let free. And, they will be given the facility of haircut and, finally, the banks will be handed over through privatization in the hands of the same people who have pilfered the bank money and have made our banking system bleed.

So, my humble request to the hon. Minister is to kindly consider this position. I welcome that the banks should be empowered. To that extent, this Ordinance as well as Bill has facilitated that arrangement but, partially, with a defect. Make banks directly responsible and directly accountable. Empower them to invoke Insolvency and Bankruptcy Code on those debtors who are making the bank bleeding. Sir, kindly take note and scrutinise those who are now responsible for the NPAs, I mean those 50 companies. You are not bringing them in public domain. You have a political problem, I understand. But the fact is that in the big companies having multiple businesses, in a group of companies, one company is suffering with NPAs while other companies are still enjoying loan from the banking system. They are still getting loans from the banking system.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now please conclude.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I am just concluding.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, one second. Among the concerned Cabinet Minister and the two MoS, none of them are present. There are two MoS and one Cabinet Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): They are taking notes. ....(*Interruptions*).. Other Cabinet Ministers are there and they are taking notes.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, there are two MoS. Not even one is present.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY; AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI PIYUSH GOYAL): Hon. Vice-Chairman, the Finance Minister is in the other House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): They are taking notes. Now please conclude, Mr. Sen.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): We are noting with concern what you all are saying, but you are not noting what we are noting.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my suggestion is that make the names of those 50 borrowers available in the public domain. While the Government will be exercising monitor's role, people should also be allowed to monitor the situation. Directly empower the banks. Don't keep the RBI in between. Let the Government and the Ministry direct the bank, and, accordingly, the Bank Boards be made responsible. In the Bank Board, the representative of the Ministry should also remain. The Bank Boards be made directly responsible to invoke the Insolvency and Bankruptcy Code on the loan defaulters. With that only, we will quicken up the process of recovery, at least, to some extent, of the people's money which is deposited in the banks and teach those crooks a lesson. That is my only request. I urge upon you to accept my Amendments on that issue.

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम (ओडिशा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज देश के बैंकों की स्थिति को देखते हुए और NPAs में हो रही वृद्धि को सुधारने के लिए यह बिल लाना बहुत ही जरूरी था। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

सर, हमारे देश में बैंक लोन डिफॉल्ट एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां NPA सबसे ज्यादा है। अगर हम NPA की बात करें, तो यह साढ़े नौ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है और इसकी वजह से बैंक दिवालियापन की ओर बढ़ रहे हैं। जो चुंनिदा उद्योगपति हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो करीब 12-13 हैं, उनके ऊपर ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का NPA है, यानी पूरे NPA का एक-चौथाई लोन उनके ऊपर है। इसको बैंक उनसे वसूल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह बहुत चिंता की बात है।

सर, कानून में संशोधन पहले भी कई बार किया गया है और नया कानून भी बनाया गया है, लेकिन NPA की समस्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। अभी इस बिल के माध्यम से जो आरबीआई को और अधिकार दिए जा रहे हैं कि वह Insolvency Code के माध्यम से stressed assets पर लगाम लगाये।

सर, हमें यह देखना पड़ेगा कि असली समस्या कहां पर है? मेरे विचार में बैंक में corruption और vested interest इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। जो कारपोरेट्स हैं, जो अमीर लोग हैं, वे बैंकों के साथ सांठगांठ करके, नियमों में हेरफेर करके बैंकों का पैसा हड़प जाते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो उनकी मेहनत की कमाई है, जो उनके द्वारा सेंविग की जाती है, उसको वे लोग हड़प लेते हैं। जो बड़े-बड़े कारपोरेट्स हैं, जो कम्पनीज़ हैं, जैसे स्टील कम्पनी के बारे में एक माननीय सदस्य ने बताया है। उनसे अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। आप भूषण स्टील कहें, ESSAR स्टील कंपनी कहें, LANCO कहें, ऐसी और भी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, जिन से अभी तक रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन यदि किसी गरीब ने 5 हजार या 1 हजार रुपए का भी लोन लिया है, तो उससे रिकवरी के लिए बैंक के मैनेजर और अफसर भेजे जाते हैं।

सर, प्रधान मंत्री जी की जन-धन योजना के अंतर्गत 28 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं और उनके माध्यम से 40 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं। अब अगर वे रुपए अमीर लेकर चले जाएं,

[श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम]

तो उसका लाभ गरीबों को नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बिल के माध्यम से ऐसे लोगों को कड़ी-से-कड़ी सज़ा देने के लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगी। सर, non official figures के हिसाब से NPA धीरे-धीरे बढ़कर 15 लाख रुपए हो रहा है, यह चिता की बात है। यह किस वजह से हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है यह तय किया जाना चाहिए ताकि आगे से ऐसा न हो पाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब समाप्त कीजिए।

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम: सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रही हूं। सर, सभी मेंबर्स ने ऐसे उद्योगपतियों के नाम का खुलासा किए जाने की बात कही है, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्ज लेकर बैंक्स को डुबोया है। यह बहुत ही चिंता की बात है। उनके खिलाफ सख्त कठोर दंड का विधान किया जाए।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह विधेयक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का और संशोधन करने के लिए लाया गया है, जिसके फलस्वरूप बैंककारी प्रणाली में दबावयुक्त आस्तियां या गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए), जो अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तरों पर पहुंच गयी हैं, उन्हें सुधार कर बैंकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकेगा। साथ ही, यह विधेयक एनपीए के समाधान के संबंध में बैंककारी कंपनियों को निर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को शक्ति प्रदान करता है।

महोदय, आज बैंकों के बढ़ते एनपीए की स्थिति को सुधारने व दिवाला समाधान प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए यह संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है। महोदय, बढ़ते एनपीए की वजह से, जोकि लगभग 9 लाख करोड़ रुपए है, बैंक दिवालिए हो रहे हैं और देश के चुंनिदा उद्योगपतियों पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसे बैंक्स वसूल नहीं कर पा रहे हैं। यह बैंकों के कुल एनपीए का लगभग एक-चौथाई है। शायद इस संशोधन के बाद रिजर्व बैंक सख्ती से बैंकों को निर्देश देकर पैसा वसूली कर सकेगा। अब शायद रिजर्व बैंक, बैंकिग सेक्टर को ज्यादा अनुशासित कर सकेगा और वह सरकार के प्रति जवाबदेह होगा।

महोदय, मैं एनपीए के कारणों की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, परंतु इस चौपट वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से आशा है कि वित्तीय प्रबंधन में आवश्यक सुधार हो सकेगा तथा एनपीए को कम किया जा सकेगा और हमारे बैंक्स आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे, इस से देश आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा और परिणामस्वरूप हमारे देशवासियों का भला होगा।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि बैंकिग प्रणाली को मजबूत व पारदर्शी बनाने के साथ-साथ, जवाबदेह भी बनाएं क्योंकि जब तक बैंक प्रणाली जवाबदेह नहीं होगी, तब तक ऐसे ही ढुलमुल तरीके से कामकाज होता रहेगा। अतः हमें बैंकिग व्यवस्था को जिम्मेदार बनाना होगा ताकि एनपीए को काबू किया जा सके और उसकी भरपायी सुनिश्चित हो सके।

महोदय, बैंकिग प्रणाली को लेकर मेरी कुछ आशंकाएं इस प्रकार हैं। महोदय, अभी बैंक डिपॉजिट व लोन पर ब्याज दर में काफी अंतर है। मुझे लगता है कि लोन पर ब्याज दर कम करने की आवश्यकता है, जिस से defaulters की बढ़ती संख्या, जोकि 8000 है, कम हो सके और लोग समय पर किश्त चुकाएं। दूसरे, अभी बैंक्स में "कार्यकरण खर्च" सब से ज्यादा है, जिस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। तीसरे, सरकार defaulters की बढ़ती संख्या को कैसे कम करेगी और बड़े defaulters के खिलाफ क्या कार्यवाही प्रस्तावित है, जिस से ऋण की वसूली हो सके। क्या ऐसे कर्जदारों के नाम सार्वजनिक करने का भी कोई प्रस्ताव है?

महोदय, हमारे देश में कई बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जो करोड़ों-अरबों रुपए लेकर भाग गए हैं। उन पर तो कार्रवाई होती नहीं है, किंतु जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, यदि वे अपनी खेती के लिए लोन लेते हैं और यदि किसी कारणवश वे लोन नहीं दे पाते हैं या मजदूर लोग अपने कारोबार के लिए या छोटे व्यापारी अपने कारोबार के लिए लोन लेते हैं, यदि किसी कारणवश जमा नहीं कर पाते हैं, तो उन गरीबों के खिलाफ डुग्गी पिट जाती है, गांव में मुनादी करा दी जाती है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है और बेइज्जत कर दिया जाता है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन बड़े-बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूला जाए, जिनके पास अरबों, खराबों रुपया है। यदि उनसे पैसा वसूला जाएगा, तो किसानों पर कम भार पड़ेगा।

यदि हमें अपने देश की तरक्की करनी है, तो हमें किसानों की तरफ ध्यान देना होगा, मजदूरों की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की गांवों से होकर गुजरती है। जब गांव खुशहाल होंगे, शहर खुशहाल होंगे, तो हमारे देश की तरक्की होगी, इसलिए हमें किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की जो घोषणा की है, वह खाली खोखली है, अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): कृपया समाप्त कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री वीर सिंह: महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट और लूंगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): मेरे पास एक मिनट नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री वीर सिंह: इसलिए हमें किसानों और मजदूरों की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): धन्यवाद।

श्री वीर सिंह: महोदय, चिट फंड कम्पनी घोटाले व पनामा सूची में आए डिफॉल्टर्स से सरकार कैसे निपटेगी व उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? इन्हीं सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Dr. Narendra Jadhav; Dr. Narendra Jadhav, we don't have much time left. Please conclude within two minutes.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Okay, Sir. What the Banking Regulations (Amendment) Ordinance, 2017, does is, essentially, to authorize the Reserve Bank of India to direct banks to initiate recovery proceedings against the loan defaulters.

[Dr. Narendra Jadhav]

Now, what is wrong with this is, this should have been done much earlier. Better late than never!

Mr. Vice-Chairman, Sir, we are facing a grave situation. On the one hand, under the Banking Regulations (Amendment) Ordinance, promulgated on 4th May, 20117, the RBI used its powers to identify 12 defaulters, each having an outstanding amount of more than ₹ 5,000 crores. Apparently, there is remorse on the part of these big-time defaulters. We all know that some of them have fled abroad and are mocking the Indian judicial system from abroad, while one of the defaulters has challenged the very constitutionality of the RBI's directions. On the other hand, in several parts of the country, small farmers have been committing suicides for their inability to pay small debts to the banks. Sir, I ask: have we become so insensitive that this grave irony doesn't touch our conscience? The situation must change, and change it must. And, this Bill is a very good step in that direction.

Sir, there are two main objections being raised while opposing the Banking Regulations (Amendment) Bill, 2017. The first objection is that this Amendment is superfluous because the powers being given to the RBI under the Bill already exist in the 1949 Act, especially Section 35A. To some extent, this is true, but isn't it amply clear that the existing provisions as well as the mechanisms have not worked as expected, as can be seen from the ballooning of the Non Performing Assets.

Sir, how long are we going to subject ourselves to what Economist Cairns called the 'tyranny of the status quo ante'? It is about time that we strengthened the hands of the RBI to address this serious problem. The proposed amendment is a major step in that direction and must, therefore, be strongly supported. ...(*Time-bell rings*)... Sir, I would take half-a-minute.

The second objection is this. A question is being asked – this was raised by my friend, Mr. Jairam Ramesh and others: Since RBI is a banking regulator, is it appropriate for a banking regulator to direct banks on specific business decisions such as recovery of loans from specific defaulters? This objection is entirely invalid in my opinion. If you look at the old documents, particularly the First Five Year Plan document, you would see that unlike Central Banks in other developed countries, in India, the role of the Reserve Bank of India as the Central Bank has never been confined to that of a regulator alone. But it is also concerned with the developmental aspect of the financial system which has invariably entailed the RBI issuing specific directions to the banks as a part of the monetary policy and financial stability considerations.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

DR. NARENDRA JADHAV: There is nothing inappropriate about it. With these remarks, I whole-heartedly support the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017. Thank you.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I, on behalf of my Party, rise to support this Bill. What is really the cause of concern is the steady increase in NPA levels year after year. In fact, the hon. Finance Minister is sitting here. As per the data that has been released by the RBI in 2008, the Non-Performing Assets were only about 2.3 per cent of the total advances given. In 2016, 2.3 per cent went up to 7.5 per cent. As per the RBI data that has been released recently, the NPA levels are expected to go up to 12 per cent by end of this 2017 which is really alarming and a cause of concern. Sir, what is the impact of this steady increase in NPA level, which may be as high as 12 per cent? I can confidently say that a majority of the banks would get into losses. Sir, despite the fact that the Government of India has taken some measures to maintain the financial stability of the banks, still the NPA levels are going up. There was demonetisation. Because of demonetisation, there is an inflow of cash from the economy into the banks. That has facilitated only the liquidity of the banks, but didn't improve the profitability of the banks. There is a scheme, namely, *Indradhanush* Scheme wherein the Government of India has to pump about ₹ 70,000 crore every year, since 2016 to 2019. Even then, the profitability of banks would still remain the same. Sir, as the hon. Finance Minister himself is an eminent advocate and has wide experience in the field of finance and two Chartered Accountants are sitting here as Cabinet Ministers, I would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister one fact. Sir, if the Statutory Central Auditors have to accept the recommendations of the Branch Auditors in so far as bad debts are concerned. If all the recommendations are to be accepted and provisioning for bad and doubtful debts are to be made in the Statutory Books of banks, I can confidently say that a majority of banks, as of today, would only be into the losses. That is the real scenario. What is there in reality is far from what is projected to be.

Sir, the second point which I would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister is regarding the Financial Stability Report published in June by the RBI. This Report ominously noted that a credit shock is likely to impact the capital adequacy and profitability of a significant number of banks. ...(*Time-bell rings*)... Sir, one more point. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No time; finish it now, please.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, the banks face one issue. When a debt becomes NPA, the banks will face the problem in deciding whether it has to be treated as NPA, whether a provisioning has to be made or restructuring of loan has to be done. Bankers will have these three options. Under the new provision, the RBI can set up a Committee to help the banks. That is what the new provision is.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; all right.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, this will expedite the process and remove the operational bottlenecks for banks. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri D. Raja. ...(*Interruptions*)... What can I do? It is already 5.20 p.m.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: I was not even given three minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken four minutes. Look at the watch. Now, Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, as I understand, the purpose of this legislation is to empower the Government to authorise the Reserve Bank of India to issue directions to the banks for initiating proceedings in case of default in loan payment. These proceedings would be initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Sir, a majority of the NPAs, that is, 88 per cent, is in the public sector banks, where the Central Government is the majority shareholder. I can argue that the Government could have initiated recovery proceedings against defaulters without having authorised the RBI. Now, the Government, in its wisdom, has decided to empower the RBI instead of directly acting against the defaulters.

Sir, the banks and banking network constitute the central nerve system of any economy. That is why when banks were nationalised in July, 1969, by the then Indira Gandhi Government, we all welcomed that move and we supported that move. But now, there is a strong apprehension that the public sector banks are going to be weakened further and the Government's equity will be reduced and finally, these banks will be de-nationalised and handed over to private hands. The Finance Minister can explain this issue.

In this connection, I would like to suggest that the Finance Minister must take the employees into confidence because they are the real primary workforce in the banking sector and they know what is happening inside the banks and how credit

policy is implemented. When students take loans and don't repay the loans, they are penalised and there have been several suicide cases because of education loans to students. They cannot pay back the loans and the banks put out notices announcing their names and photographs. But when it comes to corporate houses, big business houses, this is not done.

Sir, when Mr. Jaitley took over as the Finance Minister, the NPAs, in 2014, stood at ₹ 2,16,739 crores. But, as on 30th September, 2016, the NPAs were ₹ 6,30,323 crores. It is growing. Now, the amount must be more. In this connection, I would like to draw your attention to the fact that All India Bank Employees Association, which is the largest employees union in the banking sector, has been demanding that the Government should publish the names of the defaulters. It has been asking the Government to take tough action to recover bad loans. It has been demanding to declare the names of wilful defaulters and treat wilful default as a criminal offence. Why is the Government not doing so? ...(*Time-bell rings*)...

Finally, Sir, why do people doubt political will and determination of the Government? The Government is not acting. Panama papers were referred to. Probe on Panama papers led to the removal of the Head of the Government in Pakistan, removal of the Head of the Government in Iceland, removal of the Ethics Committee Member of FIFA, removal of the Executive Board Member of ABN AMRO, but nothing is happening in India. ...(*Time-bell rings*)... That is where the Government should show some political determination and will to take action against wilful defaulters. ...(*Time-bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Tiruchi Siva, please take only three minutes.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, this Bill allows the Reserve Bank of India to give directions to the banks to initiate action for recovery of the NPAs. My pertinent question, realizing the time constraint, is as to what was the necessity for an Ordinance. Secondly, why must RBI be entrusted with this task? Can the Government not achieve this objective through the existing mechanism of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016? Moreover, Sir, 88 per cent of the NPAs are in public sector banks, to which the Government can, of course, issue directions. We have an apprehension and we are saying that the RBI need not be entrusted with this task because the RBI is a policy institution and giving this role to the RBI enables it to perform business functions which may act as an initiation of its expanding business role rather than policy role. Sir, the RBI must be given only the role for issuing guidelines and not directions. This also exposes the RBI to be moved to courts in case of any dispute regarding NPAs. We suggest that you differentiate the role of

[Shri Tiruchi Siva]

the RBI from that of ordinary banks. The Bill should focus on addressing the NPA issue and how banks can effectively deal with it.

One suggestion which I would like to make to the Minister is this. I also spoke to him personally. Since the intention of the Bill is to come down very heavily on the NPAs, kindly exempt the education loan from coming under NPAs. Student loans amount to only 6.9 per cent of the NPAs. At least 70 per cent of the *dalit* and backward students are getting these loans and the loan amount is only five lakh rupees. If they come under NPA, they will be brought under CIBIL and that prevents or bans them from getting further loans.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I understood your point.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we say that this country is rich with youth population. And if the youth, who has defaulted in repaying his education loan, intends to start a small-scale industry or become an entrepreneur, he would be denied the loan and this would increase unemployment and there will be anarchy. I request the Minister to have another nomenclature for it. ...(*Time-bell rings*)... Kindly don't bring education loan under NPAs and save students from disaster. Thank you very much, Sir.

RESIGNATION BY MEMBER

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform the Members that the hon. Chairman has received a letter dated the 10th of August 2017 from Shri M. Venkaiah Naidu, Member, representing the State of Rajasthan, resigning his seat in the Rajya Sabha. The hon. Chairman has accepted his resignation with effect from 10th of August 2017.

GOVERNMENT BILL — *Contd.*

The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am extremely grateful to all the Members who expressed a very serious concern as far as rising NPAs are concerned. In fact, Mr. Jairam Ramesh made a very elaborate opening speech. I do agree with him on a large number of points that he stated. There is nothing wrong, as he rightly said, with loans being given. There is nothing wrong in banks then trying to effect, as per their due process, the recovery of those loans because it is only on the strength of banking finance that business expands, jobs are created and the economy moves on. But the loans have to be serviced. And as long as a loan is a service, the asset